हमारा दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक उद्धव ठाकरे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते

अशोका एक्सप्रेस

SMA - Ashoka Express Publication

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती
प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 27 ● अंक : 26 ● नई दिल्ली ● 16 से 22 जुलाई 2024 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

गुजारा भत्ता वाले फैसले पर बोले एआईएमपीएलबी सदस्य कमाल फारूकी

सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश सही हों, ऐसा मुमकिन नहीं

कोर्ट का फैसला इस्लामिक नजरिए से मुमकिन नहीं : कमाल फारुकी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब से एक मामले में मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है, तब से ही इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है. मुस्लिम संगठनों की तरफ से कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया है. इसमें सबसे आगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) है. इसके सदस्य कमाल फारुकी ने कहा है कि एआईएमपीएलबी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है. कमाल फारुकी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर सही होते हैं और उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता है. इस्लाम में मर्द और औरत, दोनों के हक को बड़े विस्तृत ढंग से बताया गया है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में कहा गया है कि जब तक बीवी आपके साथ है, आप उसका हर तरह से ख्याल रखें. ऐसा शादी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक करना होता है. इस तरह से जब तक कोई औरत किसी की बीवी है, तब तक उस मर्द पर उसकी सारी जिम्मेदारी है. एआईएमपीएलबी के सदस्य कमाल फारुकी ने आगे कहा कि तलाक के समय मेहर की रकम देनी होती है. इस्लाम में औरत को भी ताकत दी गई है कि वह तलाक का केस फाइल कर सके. सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामिक नजरिए से मुमकिन नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में तलाक को सबसे यादा खराब बताया गया है. जब दो लोग एक-दूसरे को तलाक देते हैं तो आसमान हिल जाता है.

नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर कार्रवाई करें, बातें नहीं : कांग्रेस

नई दिल्ली ।

कांग्रेस ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विशेष राय के दर्जे को लेकर सिर्फ बातें करने का आरोप लगाया और कहा कि वह वर्तमान समय में इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में हैं और इसे लेकर उन्हें पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर भी यही बात लागू होती है। बिहार सरकार के मंत्रियों ने रविवार को दावा किया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की राज्य सरकार की मांग की पुष्टि की है। नीति आयोग ने 12 जुलाई को 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। कुछ पैमानों पर स्थिति में सुधार के बावजूद इसमें बिहार सतत विकास का आकलन करने वाले 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स पर पोस्ट किया, ''बिहार के वरिष्ठ मंत्री अब बोल रहे हैं कि नीति आयोग का ताज़ा विश्लेषण, राज्य को केंद्र की तरफ़ से मिलने वाली सहायता के मामले में विशेष राज्य के दर्ज़े समेत उनकी अन्य मांग को सही ठहराता है।

अन्य फ़ायदों के अलावा, इसका मुख्य रूप से यह मतलब है कि ऐसी सहायता का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में होने के बजाय, केवल 10 प्रतिशत होगा। उन्होंने सवाल किया कि मीडिया में बयान देने और पार्टी की बैठकों में प्रस्ताव पारित करने के बजाय बिहार के मुख्यमंत्री इस मांग को लेकर क्या कर रहे हैं कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार को जनता दल (यूनाइटेड) के 12 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की अहम भूमिका का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए दावा किया, ''नीतीश कुमार ने इसे लेकर किया कुछ नहीं है। वह अब तक सिर्फ़ बातें बनाते आ रहे हैं। रमेश ने कहा, ''नीतीश अब इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में हैं। उन्हें पूरी ताक़त लगा देना चाहिए। यही बात आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू होती है।

बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति न हो

नई दिल्ली । कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाए जाने के बाद सोमवार को उस पर पलटवार किया और कहा कि नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ झूठ फैलाकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के विरुद्ध भड़का रहे हैं। भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने रविवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर हमले के बाद राहुल गांधी पर निशाना साधा था और विपक्ष के नेता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया था। खेड़ा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर घटिया राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी को दक्षिणपंथी आतंकवादियों के हाथों खो दिया। हमने आतंकवादियों के हाथों दो प्रधानमंत्रियों को खो दिया।भाजपा सरकार में हमने अपना संपूर्ण छत्तीसगढ़ नेतृत्व नक्सलवादियों के हाथों खो दिया। उन्होंने दावा किया, प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा लोगों को नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे गांधी परिवार के खिलाफ झूठ फैलाकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्होंने रहस्यमय तरीके से उनकी एसपीजी सुरक्षा भी वापस ले ली।

केशव प्रसाद ने सपा को बताया सांपनाथ तो कांग्रेस को नागनाथ, बोले- विपक्ष हमारे मनोबल के आगे नहीं टिक सकता

लखनऊ।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 300 से यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चलना है। इसके लिए जरूरी है कि मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं को सम्मान दें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। पहली बार उड़ीसा में जय जगन्नाथ हुआ है। सिक्किम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2014 में मोदी की सरकार बनाई, 2017 में प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाकर सरकार बनाई। 2019 में फिर मोदी की सरकार और 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हालांकि, वर्ष 2024 में तमाम प्रयासों के बावजूद परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। सपा और कांग्रेस रूपी सांपनाथ और नागनाथ ने झूठ और फरेब कर थोड़े समय के लिए हमें पीछे किया है, लेकिन 2027 में फिर से 300 पार लक्ष्य के साथ प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का भाव हनुमान जैसा है। वह थोड़े समय के लिए सपा व कांग्रेस के झूठ और के कारण अपनी शक्ति को भूला है। 2027 में वह दोबारा वह अपने सामर्थ्य से विपक्षी गठजोड़ को पराजित करेगा। 2014 और 2019 में प्रदेश में सपा-बसपा गठबंधन को पराजित कर मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने में कार्यकर्ताओं का खास योगदान रहा। उन्होंने कहा कि बहकावे और झूठ का फर्क समझना है। भाजपा विकास के लिए काम करती है। झूठ की मशीन बन चुके विपक्ष को जवाब देने का समय आ गया है। वो हमारे मनोबल के आगे नहीं टिक सकते, 2024 में जो कमी रह गई है उसे 2027 में प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनाकर अपनी ताकत को साबित कर देंगे। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की बैठक में यह तय करके जाना है कि 2027 में सपा बसपा और कांग्रेस एकजुट हो जाएं तो भी हमें अपने सामर्थ्य के बल पर 300 पार के लक्ष्य को पार पाना है।

ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की याचिका को टाला, अगली सुनवाई 7 अगस्त

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत को लेकर कड़ा विरोध किया। इस कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई को टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को 20 जून को दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने फिर 25 जून को इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रोक लगा दी थी।

केजरीवाल ने हाईकोर्ट में 10 जुलाई को उत्तर दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बयान दिया कि उनकी जमानत को रद्द करना न्याय की विफलता होगी और उन्होंने अपने आत्मसमर्पण का इरादा दिखाया। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा भी एक और मामला चल रहा है, जिसमें उन्हें शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। इस तरह, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ न्यायिक लड़ाई जारी है, जिसमें वह अपनी बेनाक़ाबी करने के लिए तैयार हैं। यह मामला राजनीतिक घमासान का केंद्र बन गया है, जिसमें न्यायिक तंत्र की आजादी का सवाल उठ रहा है।

सम्पादकीय

छात्रों को किफायती मैडीकल कॉलेज दरकार हैं

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरी मैडीकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यू.जी.' 2024 को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सख्त रूप अपनाया है। माननीय सी.जे.आई. चंद्रचूड़ जी ने कहा, ''पेपर लीक पर विवाद नहीं किया जा सकता। हम इसके परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं। हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं, लेकिन दोबारा परीक्षा पर निर्णय लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि हम 23 लाख छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं।'' माननीय सुप्रीम कोर्ट की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर टिप्पणी अत्यंत संजीदा है और यह हमारे छात्रों के भविष्य को लेकर ड्क्षचताओं की अभिव्यक्ति भी करती नजर आ रही है। प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण छात्रों और अभिभावकों का विश्वास क्यों डोल रहा है इससे जुड़े कुछ तथ्य विचारणीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार, देश की युवा आबादी (15-29 वर्ष की आयु) में बेरोजगारों की संख्या 83 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों के बेरोजगारों की संख्या 'बहुत खराब' है। संयोग से ये राज्य पेपर लीक के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे ड्क्षहदी भाषी राज्यों में पेपर लीक की बढ़ती समस्या काफी हद तक स्थिर आर्थिक माहौल का प्रतिबिंब है, जहां रोजगार के अवसर सीमित हैं। देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से के राज्यों की तुलना में इन राज्यों में कोई समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, जहां निजी क्षेत्र रोजगार प्रदान करने में आगे आ सकता है। इन राज्यों में पेपर लीक के मूल में इनकी कमजोर अर्थव्यवस्था है, जो पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजग़ार के अवसर पैदा करने में विफल हो रही है, जिससे सरकारी नौकरियों की मांग बढ़ रही है। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश से पेपर लीक की 8, राजस्थान और महाराष्ट्र से करीब 7-7 और बिहार से पेपर लीक की 6 खबरें सामने आई हैं, जिसमें 2023 के कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती परीक्षा भी शामिल हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में करीब 4 मामले सामने आए हैं। पेपर लीक कांड का एक कारण देश में मैडीकल कॉलेज कम होना भी है। देश में मैडीकल शिक्षा की आपूर्ति की बात करें तो इस वक्त मैडीकल शिक्षा जैसे स्ट्रीम पर बहुत ज्यादा बोझ है क्योंकि अन्य विकल्प जो नए जमाने की स्किल प्रदान कर सकते हैं और युवाओं को डिजिटल मार्कीटिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे नए उद्योगों में रोजगार योग्य बना सकते हैं, जो अभी तक पर्याप्त संख्या में नहीं खुले हैं। नीट जैसे मामलों का पैदा होना इसी मांग और आपूर्ति में फासले के कारण भी है। आजादी के बाद से ही सरकारी कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. सीटों के लिए विशेष रूप से अभूतपूर्व मांग रही है। इसलिए, जब कथित पेपर लीक का मुद्दा सामने आया है तो , तो इसने भारत में मैडीकल एजुकेशन के सामने आने वाली चुनौतियों और एन.टी.ए. के भीतर के मुद्दों की ओर ध्यान आर्ज्षित करना तर्क संगत है।

विश्व स्तर पर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का लक्ष्य रखता है

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक सांझेदारी को मजबूत करना था। रूस के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने इसे अशांत भू-राजनीतिक माहौल के बीच 'ऐतिहासिक और खेल बदलने वाला' बताया। मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन ने दो प्रभावशाली देशों रूस और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ संबंधों के लिए मोदी के कुशल प्रबंधन को उजागर किया। रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध के बावजूद, दोनों नेताओं द्वारा अपनी बैठकों के दौरान दिखाई गई गर्मजोशी मोदी की रूस यात्रा के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। मोदी पिछले 10 वर्षों में 6 बार रूस का दौरा कर चुके हैं और कम से कम 17 बार पुतिन से मिले हैं। इस यात्रा के दौरान पुतिन के निजी आवास पर रात्रिभोज पर बातचीत साढ़े 4 घंटे तक चली, जबकि आमने-सामने की बातचीत अढ़ाई घंटे तक चली। इससे दोनों नेताओं को मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला। वर्तमान यात्रा ने भारत और रूस के बीच स्थायी संबंधों और पुतिन के साथ आमने-सामने की चर्चा को उजागर किया। इसमें चीन और घरेलू राजनीतिक स्थिति भी शामिल है। शिखर सम्मेलन ने यू.एस.-भारत संबंधों के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। यह ऐसे असुविधाजनक समय पर हुआ जब यूक्रेन में संघर्ष जारी था। बैठक का प्रभाव यह था कि भारत रूस और यू.एस. के साथ संबंधों को संभाल सकता है। मोदी का पुतिन के साथ 'गले मिलना' और पुतिन द्वारा मोदी को अपना 'सबसे अच्छा दोस्त' कहना शायद यू.एस. और पश्चिम में भौंहें चढ़ा सकता है। सी.एन.एन. ने कहा, ''व्लादिमीर पुतिन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आवास पर मिनी इलैक्ट्रिक कार में घुमाने का दृश्य दिखाता है कि दोनों नेता कितने घनिष्ठ हो गए हैं।'' इस यात्रा ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया। इसने विज्ञान, व्यापार और जलवायु परिवर्तन पहलों सहित नए समझौतों का मार्ग प्रशस्त किया। भारत और रूस का लक्ष्य पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन तक बढ़ाना है। प्रस्तावित नए परमाणु रिएक्टरों सहित भारत का ऊर्जा भविष्य आशाजनक था। जिस तरह से नई दिल्ली रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकती है, वह आशावाद की भावना प्रदान करता है। बाइडेन प्रशासन द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत की महत्वपूर्ण सांझेदारी की पुष्टि आश्वस्त करने वाली है। यह अमरीका-भारत के बढ़ते संबंधों की मजबूती और स्थिरता को रेखांकित करता है। कई अमरीकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। उदाहरण के लिए, पेंटागन के प्रैस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि अमरीका भारत को एक रणनीतिक सांझेदार के रूप में देखता है और मजबूत संवाद में शामिल रहेगा। इस संवाद में रूस के साथ भारत के संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा शामिल है।

अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका यूक्रेन में स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत को प्रोत्साहित करना जारी रखता है। उन्होंने यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने में भारत के समर्थन के महत्व पर जोर दिया। भारत ने हाल के वर्षों में रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। रूस भारत के हथियारों का प्राथमिक स्रोत होने के बावजूद, नई दिल्ली ने संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस और इसराईल से भी अधिक हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। भारत अपनी तोपों की खरीद के लिए अपने विकल्पों का विस्तार कर रहा है। मोदी की यात्रा के दौरान, किसी नए हथियार सौदे की घोषणा नहीं की गई। हालांकि, विशेषज्ञ भारत में अमरीकी राजदूत एरिक गार्सेटी के हालिया भाषण का विश्लेषण कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि भारत-अमरीका संबंध मजबूत हैं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष के दौरान भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत और रूस वैश्विक राजनीति में अलग-अलग रास्ते अपना रहे हैं। भारत संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर और उसकी इंडो-पैसिफिक रणनीति को अपनाकर पश्चिम के करीब जा रहा है। दूसरी ओर, रूस खुद को भारत के प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ और अधिक निकटता से जोड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, रूस का लक्ष्य ब्रिक्स जैसे समूहों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। भारत ब्रिक्स, एस.सी.ओ. और इंडो-पैसिफिक क्वाड का हिस्सा है। इसका लक्ष्य वैश्विक दक्षिण और विकसित दुनिया के बीच की खाई को पाटना है। इसके विपरीत, रूस यूक्रेन युद्ध में तेजी से शामिल हो रहा है और पश्चिम से अलग-थलग पड़ रहा है। नई दिल्ली ने यूक्रेन युद्ध की आलोचना नहीं की है, लेकिन इसे रोकने के लिए कहा है। रॉयटर्स के अनुसार, मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल पर हुए जानलेवा हमले के अगले दिन मंगलवार को पुतिन की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना की। मोदी ने पुतिन से कहा कि मासूम बच्चों की मौत दर्दनाक और डरावनी है। भारत महत्वाकांक्षी हो गया है और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का लक्ष्य रखता है। नई दिल्ली इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने का इरादा रखती है। साथ ही, हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन ने एक मजबूत संकेत दिया है।

गर्भवती महिलाओं, शिशुओं का दम घोंटती जहरीली हवा

हवा में घुले जहर में गर्भवती महिलाओं और नवजातों का दम घुट रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 2 सालों में दिल्ली-एन.सी.आर. में घनी धुंध और भारी वायु प्रदूषण की अवधि 4 महीने से बढ़कर 6 हो गई है। नवजात शिशुओं में जन्म के साथ सांस संबंधी परेशानियां सामने आ रही हैं। जहरीली हवा से गर्भवती महिलाओं के प्रसव में दिक्कतें बढ़ी हैं। लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहने से गर्भावस्था में महिलाओं कें ऑक्सीजन लैवल घटने के कारण तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा में हुए एक हालिया अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि हवा में पी.एम. का स्तर बढने से गर्भवती महिलाओं और नवजातों पर सीधा असर पड़ता है। अध्ययन में देखा गया कि जो महिलाएं गर्भकाल में ज्यादा प्रदूषित क्षेत्र में रहीं उनसे जन्मे बच्चों की सांस में भारीपन, अविकसित फेफड़े और जन्मजात टी.बी. पाई गई है। इन महिलाओं को भी अन्य गर्भवतियों से ज्यादा दिक्कतें झेलने पड़ी हैं। जबकि प्रदूषण रहित हवा में समय गुजारने वाली मांओं, बच्चों की सेहत तंदुरूस्त निकली। अध्ययन से पता चला है कि प्रसव के दौरान मां के वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से नवजात में जन्म के तुरंत बाद सांस संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। यह अध्ययन कनाडा स्वास्थ्य विभाग 'हैल्थ कनाडा' और पेन स्टेट कॉलेज ऑफ मैडीसिन से जुड़े शोधकर्त्ताओं द्वारा किया गया है, जिसके नतीजे जर्नल एनवायरनमैंटल हैल्थ पर्सपैक्टिव्स (ई.एच.पी.) में प्रकाशित हुए हैं। पूरी दुनिया में नवजातों में जन्म के फौरन बाद सांस से जुड़ी दिक्कतों और जल्दी मृत्यु का एक अहम कारण सांस से जुड़ी परेशानियां हैं। लेकिन क्या दूषित हवा इसके लिए जिम्मेदार है और वह इसे कैसे प्रभावित करती है। इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। चिकित्सकों की मानें तो गर्भावस्था के दौरान मांओं के वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से उनके बच्चों में अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यह समस्याएं कई दफा काफी लम्बे समय में सामने आती हैं। भारत में नवजातों पर वायु प्रदूषण के पड़ते प्रभावों को

लेकर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में ओजोन प्रदूषण का संपर्क जन्म के समय नवजातों के वजन में कमी की वजह बन रहा है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि इन प्रदूषक तत्वों की वजह से भ्रूण को इतना नुकसान पहुंचता है कि समय से पहले बच्चे के जन्म का खतरा बढ़ जाता है। 2 साल पहले लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया था कि वायु प्रदूषण का गर्भपात से सीधा संबंध है। अगर सरकारें दिल्ली-एन.सी.आर. समेत देशभर में वायु गुणवत्ता स्तर को सुधार लें तो 7 प्रतिशत तक प्रैगनैंसी लॉस को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण पेट में पल रहे बच्चे तक पहुंचता कैसे है, इस पर विशेषज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण की स्थिति में जब गर्भवती महिला सांस लेती है तो प्रदूषण के कण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो महिला के पेट में पल रह बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। वायु प्रदूषण मां और बच्चे को जोडने वाली गर्भनाल को क्षतिग्रस्त करके भ्रूण तक को नुकसान करता है। दरअसल, गर्भवती मां जो भी खाती है वह सीधा बच्चा भी ग्रहण करता है। डाक्टरों के अनुसार, गर्भवती महिलाओं में वायु प्रदूषण के कारण प्री-मैच्योर डिलीवरी का खतरा भी रहता है। कुछ मामलों में गर्भ में पल रहा बच्चा अस्थमा से भी पीड़ित हो सकता है। यह भी संभव है कि बच्चा जीवन भर फेफड़ों की समस्या से ही पीड़ित रहे। डाक्टरों के अनुसार हवा में घुले पीएम2.5 के स्तर में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि जन्म के समय कम वजन होने के जोखिम में 11 फीसदी का इजाफा कर सकती है। इसी तरह प्रदूषण की वजह से नवजात के समय से पहले जन्म लेने का जोखिम भी 12 फीसदी बढ़ जाता है। भारत में वायु प्रदूषण के प्रभाव से बच्चों की मृत्यु, गंभीर श्वसन संक्रमण, समय से पहले और मृत जन्म, स्टंटिंग, अनीमिया, एलर्जिक राइनाइटिस (हे फीवर) और दिमागी विकास जैसी बीमारियों के पुख्ता प्रमाण बढ़ रहे हैं। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि वायु प्रदूषण के चलते बच्चे की आंत के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करने वाले प्रदूषक आंत के रोगाणुओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिससे एलर्जी, मोटापा और मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है, यहां तक कि दिमागी विकास पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसकी वजह से भूख, इम्युनिटी और मनोदशा प्रभावित होती है। साथ ही बच्चे हृदय रोग, अस्थमा, टाइप 2 मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव के चलते भारत के साथ पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रत्येक वर्ष 3.49 लाख गर्भपात हो रहे हैं। डाक्टरों के अनुसार, गर्भवती महिलाओं में वायु प्रदूषण के कारण प्री-मेच्योर डिलीवरी का खतरा भी रहता है। वायु प्रदूषण की स्थिति में जब गर्भवती महिला सांस लेती है तो प्रदूषण के कण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जो महिला के पेट में पल रह बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात वायु प्रदूषण से भावी पीढ़ी पर बढ़ते संकट से निपटने पर हो तो इसके लिए न केवल ठोस नीतियों की जरूरत है, बल्कि इन नीतियों का कड़ाई से पालन किया जाए उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को खुद को प्रदूषण से दूर रखना होगा। ऐसे इलाकों में रहें जहां पर कम प्रदूषण हो। अगर भारत वायु प्रदूषण को कम कर लेता है तो हर साल गर्भपात के मामलों में 7 फीसदी की कमी आ सकती है।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

ट्रम्प के हमलावर की सामने आई पहली तस्वीर, स्कूल में मिल चुका है स्टार अवॉर्ड

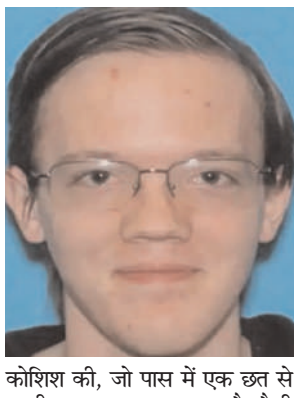

नेशनल डेस्क । रविवार 14 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में एक अभियान रैली के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कान में गोली लगने के कुछ घंटों बाद, पूरे देश में सदमे की लहर फैल गई। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने हत्यारे की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में की। एफबीआई ने एक बयान में कहा, एफबीआई ने पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की पहचान 13 जुलाई को बटलर, पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या के प्रयास में शामिल व्यक्ति के रूप में की है। जांच एजेंसी ने अब युवा हमलावर की तस्वीर जारी की है। छवि में 20 वर्षीय व्यक्ति को चश्मा पहने और कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर पास की छत से कई गोलियां चलाने के बाद सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने बदमाशों को मार गिराया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को एक व्यक्ति के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, जो पास में एक छत से दूसरी छत पर जा रहा था और रैली की ओर बंदूक तानकर पेट के बल लेटा हुआ था। उसके शव के पास एक असॉल्ट राइफल, एआर-15 पाई गई। , क्रुक्स ने 2022 में बेथेल पार्क हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, और राष्ट्रीय गणित और विज्ञान पहल से 500 का स्टार पुरस्कार प्राप्त किया था। थॉमस 2022 में इस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ था। उसे नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव से 40 हजार का 'स्टार अवार्ड' मिला था। स्कूल के पुराने साथियों ने उसे शांत और अलग-थलग रहने वाला शख्स बताया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुराने स्कूलमेट्स के मुताबिक क्रूक्स एक शांत स्टूडेंट था, जो अक्सर अकेला नजर आता था। वहीं, क्रूक्स का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहा है- मैं रिपब्लिकन से नफरत करता हूं। मैं ट्रम्प से नफरत करता हूं। क्योंकि वे गलत व्यक्ति हैं। ग्रेजुएट होने के बाद, वह एक नर्सिंग होम में काम कर रहा था। हमले के बाद, उसकी कार के अंदर एक संदिग्ध उपकरण पाया गया, जिसका अब बम तकनीशियनों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारी अब उसके फोन की तलाश कर रहे हैं। रविवार का हमला ट्रम्प के लिए एक करीबी आह्वान था, जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने की बोली के बीच में हैं। वीडियो से पता चलता है कि आखिरी सेकंड में सिर झुकाने से ट्रंप की जान बच गई क्योंकि गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। हमले के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने उसे मंच से बाहर कर दिया।

ट्रंप पर हुए हमले पर जो बाइडेन का बयान, बोले- घटना की जांच होने दें, अपनी थ्योरी न बनाएं

इंटरनेशल डेस्क ।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के एक दिन बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशवासियों से 'एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने की अपील की और कहा कि वह इस हमले से जुड़े घटनाक्रम के सिलसिले में स्वतंत्र सुरक्षा समीक्षा का आदेश दे रहे हैं।

बाइडेन ने 'सिचुएशन रूम में (प्राथमिक) जांच के बारे में जानकारी मिलने के बाद व्हाइट हाउस में संक्षिप्त बयान में यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिया है कि जांच 'सघन एवं त्वरित हो। उन्होंने देशवासियों से हमलावर के इरादे या किसी संबद्धता (संगठन या व्यक्ति से संबंध) के बारे में कोई 'धारणा नहीं बनाने की अपील की। एफबीआई और सीक्रेट सर्विस एजेंसियों को अपना काम करने दें। बाइडेन की रविवार को बाद में इस संबंध में देश के नाम विस्तृत बयान देने/जारी करने की योजना है। इससे पहले राष्ट्रपति कार्यालय ने लोगों से एकजुटता बनाए रखने का आह्वान करते हुए ट्रंप पर हमले की निंदा की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड, गृह सुरक्षा मंत्री एलेजांद्रो मयोरकास और संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक क्रिस्टोफर रे सहित शीर्ष जांचकर्ताओं से घटनाक्रम की जानकारी ली। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और 'सीक्रेट सर्विस के निदेशक किम चीटल भी बैठक में शामिल थे।

राष्ट्रपति बाइडन ने रैली में गोलीबारी की घटना की निंदा की और शनिवार रात को ट्रंप से बात की। ट्रंप के प्रचार अभियान दल के एक अधिकारी के अनुसार, शनिवार की गोलीबारी के मद्देनजर हैरिस ने मंगलवार को फ्लोरिडा की अपनी प्रस्तावित प्रचार अभियान यात्रा स्थगित कर दी है, जहां उन्हें रिपब्लिकन महिला मतदाताओं से मिलना था। ट्रंप पर पेनसिल्वेनिया में शनिवार को चुनावी रैली में एक युवक ने गोलियां चलाईं और एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में लगी, लेकिन उनकी हालत ठीक है।

भारत-मालदीवः राष्ट्रपति मुइज़ू से मिले भारतीय उचायुक्त; कहा- द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध

वर्ल्ड डेस्क। भारत और मालदीव हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के उचायुक्त मुनु महावर और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही मालदीव में भारत द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं पर बात की। भारत के उचायुक्त महावर ने रविवार को मालदीव में राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से मुलाकात की। इस दौरान महावर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सामिल होने के लिए मुइज़ू का आभार व्यक्त किया। बाद में महावर ने दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग पर प्रकाश डाला। साथ ही मालदीव के लोगों की प्रगति और विकास में सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति मुइज़ू ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार द्वारा किए गए गर्मजोशी से स्वागत और उदार आतिथ्य की सराहना की। उन्होंने मालदीव के विकास में सहायता करने और मालदीववासियों की जरूरतों को पूरा करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए भी आभार व्यक्त किया। दोनों की मुलाकात के बाद भारतीय उचायोग ने राष्ट्रपति कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति पर प्रतिक्रिया दी। एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत मालदीव के साथ अपने विशेष संबंधों को और बढ़ाने को उच महत्व देता है। बता दें कि मुइज़ू ने पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था, जिसके बाद मुइज़ू ने भारत से उपहार में दिए गए तीन विमानन प्लेटफार्मों का संचालन करने वाले लगभग 90 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा था। मुइज़ू के इस कदम से भारत और मालदीव के बीच संबंध गंभीर तनाव में आए गए थे। वहीं, भारत ने 10 मई तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेकर उनके स्थान पर एक डोर्नियर विमान और दो हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए नागरिक कर्मियों की नियुक्ति कर दी थी।

सावधान : दर्जनों कुत्तों का उत्पीड़न कर उन्हें मारने वाले शख्स को होगी 249 साल की सजा!

लंदन । शायद आप लोगों को याद होगा पिछले साल ब्रिटेन के एक मगरमछ विशेषज्ञ ने स्वीकार किया था कि उसने कुत्तों का दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, मानवता की सारी हदें पार करने वाले इस शख्स ने अपने कारनामों का ना केवल वीडियो बनाया था, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। हाल ही में इस मामले में फिर सुनवाई हुई। अदालत दोषी को सजा देने ही वाली थी कि उसके वकील ने एक नई रिपोर्ट पेश कर दी, जिसकी वजह से एक बार फिर सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त में होगी।

कई चैनलों के साथ काम कर चुका है शख्स

ऐसा नहीं है कि यह कोई अनपढ़ व्यक्ति था। बीबीसी और नेशनल योग्राफिक के साथ काम कर चुका एडम ब्रिटन एक प्रमुख प्राणीविज्ञानी है। उसने पिछली साल ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने बताया था कि दर्जनों कुत्तों को तब तक प्रताड़ित किया, जब तक वे मर नहीं गए।

सैकड़ों साल बिताने पड़ सकते हैं जेल में

उसने बताया था कि यह सब कैमरे में भी कैद किया था। इतना ही नहीं, ब्रिटन ने 60 आरोपों के बीच बाल शोषण सामग्री को ऑनलाइन एक्सेस करने की बात भी कबूल की थी। बता दें, एडम पर दुष्कर्म, यातना और दर्जनों कुत्तों की मौत का आरोप लगाया गया है। उसे 249 साल की जेल हो सकती है।

न्यायाधीश ने लोगों को बाहर जाने को कहा

स्थानीय मीडिया के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हो रही थी, तो न्यायाधीश ने लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अपराधों का उल्लेख डरावना था। इससे किसी कमजोर दिल वाले को नुकसान पहुंच सकता था। उन्होंने इस पूरे कृत्य को जानवरों के प्रति भयावह करूरता करार दिया।

नई रिपोर्ट से हलचल

जब लोग अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे थे, तभी एडम के वकील ने एक नई रिपोर्ट पेश करके हलचल पैदा कर दी। वकील ने न्यायाधीश से इस रिपोर्ट पर विचार करने का अनुरोध किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल में मनोवैज्ञानिक द्वारा करीब 30 घंटे तक उनका इलाज किया गया। इसकी रिपोर्ट में उनकी मौजूदा मानसिक स्थिति के बारे में बात की गई है। अपने मुवक्किल की सजा में कमी करने का अनुरोध करते हुए वकील ने कहा, यह एक इंसान है जो बचपन से ही इस बीमारी से पीड़ित है ... यह उसकी गलती नहीं है। यह महत्वपूर्ण है न्यायाधीश, यह विशेष बीमारी समाजों में एक अजीब सी स्थिती पैदा कर देती है। समाज के लोग ऐसे लोगों को अपने बीच में जगह नहीं दे पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अदालत यह स्वीकार कर सकती है कि वयस्क होने तक इस बीमारी के साथ जीना और इसे संभालना बहुत मुश्किल रहा होगा। इससे पहले, पिछले साल हुई सुनवाई के दौरान अभियोजकों ने कहा था कि ब्रिटन की साल 2014 से जानवरों में रुचि थी। उसने अपने पालतू जानवरों के साथ-साथ उन कुत्तों का भी शोषण किया, जिन्हें मालिकों द्वारा छोड़ दिया गया था।

शिकार करने के लिए ऐसे ढूंढता था कुत्तों को

अदालत को अभियोजकों ने बताया था कि एडम ऐसे लोगों की तलाश करता था, जो लोग काम में व्यस्त हो और अपने जानवरों को उसे दे दें। वह लोगों के सामने झूठी कहानी बताता था या पुराने मालिकों को उनके पालतू जानवरों पर अपडेट के लिए पहुंचने के लिए पुरानी तस्वीरें भेजता था। अदालत को बताया गया था कि उसने एक रूम बनाया था, जिसमें रिकॉर्डिंग टूल से जोड़कर रखा था।

इसी रूम में वह जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करता था। अभियोजकों ने इस रूम को टॉर्चर रूम कहकर बुलाया था। बता दें, जूलॉजी में पीएचडी करने वाले और चार्ल्स डार्विन विश्वविद्यालय में अकादमिक पद पर काबिज एडम ब्रिटन को साल 2022 में उत्तरी क्षेत्र की पुलिस ने ऐसी ही एक घटना का वीडियो देखने के बाद उसे गिरफ्तार किया था। अपराधी को दिसंबर में सजा सुनाई जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले, 18 महीनों में उसने 42 कुत्तों को प्रताड़ित किया, जिनमें से 39 की मौत हो चुकी है।

पीएम मोदी के लिए जन गण मन गाने वाली सिंगर अब ट्रंप के नामांकन में गाएंगी अमेरिकी राष्ट्रगान

वॉशिंगटन ।

अमेरिका में पांच नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से मैदान में हैं। उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के 81 वर्षीय मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन से है।

विस्कोन्सिन के मिल्वौकी में चल रहे चार दिवसीय रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन (आरएनसी) में ट्रंप को नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक रूप से नामित किया जाएगा। इस खास मौके पर लोकप्रिय अफ्रीकी अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन भी नजर आएंगी। वह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण से पहले अमेरिकी राष्ट्रगान गाएंगी। मिलबेन ने कहा, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की गई। वह एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और फिलहाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। इन सबसे हटकर वह मेरे दोस्त हैं। फिर भी मैं सच में ट्रंप की ताकत से प्रोत्साहित हूं। बता दें, प्रमुख अफ्रीकी-अमेरिकी हॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर मैरी मिलबेन को अक्सर संयुक्त राय अमेरिका और दुनिया भर में अमेरिका के राष्ट्रीयगान गायक के रूप में जाना जाता है। वह अब तक अमेरिका के लगातार चार राष्ट्रपतियों जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के

लिए अमेरिकी राष्ट्रगान और देशभक्ति संगीत प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भी भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन प्रस्तुत कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की जीवन की रक्षा भगवान ने की है, यह बहुत ही साफ है। ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक रूप से नामित करने से पहले गाने का मौका दिया गया है। अमेरिकियों के रूप में एकजुट होने के लिए अब हम जिस पल का सामना कर रहे हैं, वह साफ है। गायिका ने आगे कहा, राष्ट्रगान हमें याद दिलाता है कि हम सभी पहले अमेरिकी हैं।

भगवान के अधीन एक देश। रिपब्लिकन या डेमोक्रेट से भगवान को कोई मतलब नहीं है। मगर हमारा एक-दूसरे से प्यार करना मतलब रखता है। हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभ्यता की ओर लौटना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि जब मैं राष्ट्रगान गाऊं तो वो पल हमारे दिलों और आत्माओं को ईश्वर के प्रेम, हमारे देश के प्रति प्रेम, ट्रंप के प्रति प्रेम और एक-दूसरे के प्रति प्रेम से भर दे। मिलबेन भारत में तब चर्चा में आई थीं, जब भारत के स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ के लिए 2020 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रगान और दिवाली उत्सव के लिए भजन ओम जय जगदीश हरे गाकर सुर्खियां बटोरी थीं। पूरे अमेरिका और भारत में लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा था। मिलबेन को अगस्त 2022 में भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित की जाने वाली पहली अमेरिकी-अफ्रीकी कलाकार बन गई थीं।

संसद सुरक्षा चूक केस : दिल्ली पुलिस ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत चलेगा केस

नई दिल्ली । संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में अब आरोपियों को दो अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सुनवाई होगी। इस मामले में दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की मंजूरी दी है। अब पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दायर कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सात जून को इस मामले में गिरफ्तार सभी छह आरोपियों मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ करीब 1000 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था। इस मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने छह आरोपियों पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इन लोगों पर 13 दिसंबर 2023 को सदन की कार्यवाही के दौरान संसद पर कथित रूप से हमला करने का आरोप है। आरोप है कि मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम, ललित झा और महेश कुमावत नामक लोगों ने संसद में अवैध रूप से प्रवेश किया। साथ ही चालू सत्र के दौरान लोकसभा में धुएं के कैन फेंके। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उपरायपाल से यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत उनके अभियोजन का अनुरोध किया था। एलजी ने रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री पाए जाने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की। इस मंजूरी से पहले समीक्षा समिति (डीओपी, तीस हजारी, दिल्ली) ने भी 30 मई को जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए संपूर्ण साक्ष्यों की जांच की। जांच में संसद हमले के मामले में आरोपियों की संलिप्तता पाई गई थी।

इसे देखते हुए समीक्षा समिति ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला बनता है। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम की तहत एफआईआर दर्ज की। बाद में मामले की जांच संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से पीएस स्पेशल सेल, नई दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थानांतरित कर दी गई थी। जांच के दौरान उपरोक्त छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली में भाजपा का बड़ा प्रदर्शन: बिजली महंगी होने पर खोला जगह-जगह मोर्चा, मनोज तिवारी की आप को चेतावनी

नई दिल्ली ।

दिल्ली भाजपा ने राजधानी में बिजली महंगी होने के खिलाफ सोमवार को बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज हम दिल्ली के हर इलाके में, जहां भी इन बिजली कंपनियों के कार्यालय हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह उनके लिए चेतावनी है कि वे सावधान हो जाएं। अन्यथा, दिल्ली की जनता न तो बिजली कंपनियों को माफ करने वाली है और न ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को। भाजपा ने कहा कि दिल्लीवासियों को महंगी बिजली दी जा रही है, लेकिन इसका कारण बिजली खपत में बढ़ोतरी होना नहीं है। उसका आरोप है कि बिजली महंगी होने का सबसे बड़ा कारण समय रहते अतिरिक्त बिजली की खरीद न किया जाना है, जबकि इसी की आड़ में छिपकर PPAC के जरिए हर साल अप्रत्यक्ष तरीके से बिजली बिल में बढ़ोतरी की जा रही है। पार्टी सोमवार को दिल्ली के सभी जिलों में बने बिजली दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी। भाजपा के अनुसार, अब आम उपभोक्ताओं पर PPAC का बोझ 2015 में 1.5 फ़ीसदी से बढ़कर 37.5 फ़ीसदी हो चुका है। अलग-अलग कम्पनियों के द्वारा लगभग 8.75 फ़ीसदी की नई बढ़ोतरी के बाद यह 45 फीसदी तक हो जाएगा। पार्टी के अनुसार एक बार PPAC बढ़ाने के बाद इसे कभी वापस नहीं लिया जाता, जिससे इसकी मार बढ़ती जा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चेयरमैन को पत्र लिखकर PPAC पर पुनर्विचार करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों की आवाज को दिल्ली की सरकारों के कानों तक पहुंचाने का है। पार्टी यह काम पूरी जागरूकता के साथ कर रही है। कांग्रेस घरों तक पेयजल पहुंचाने, जलभराव होने, जल निकासी, बिजली कटौती, बिजली दरों में बढ़ोत्तरी, जनता से जुड़ी समस्याएं लगातार उठा रहे है और लोगों के बीच चर्चा भी कर रहे है। दरअसल जनता की परेशानियों और समस्याओं के समाधान में केजरीवाल सरकार चौतरफा विफल हो रही है।

आप का आरोप, लगातार बिगड़ रही दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति, वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त पुलिसकर्मी

नई दिल्ली । जीटीबी अस्पताल के वार्ड के अंदर मरीज की हत्या गलत पहचान का मामला हो सकता है। पुलिस को इस बात का शक है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि घटना होने से एक दिन पहले ही एक अपराधी को उसी वार्ड से स्थानांतरित किया गया था।

हालांकि, इसको लेकर दिल्ली की आप सरकार ने राजधानी में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल (एलजी) पर कई सवाल खड़े लिए है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसके लिए उपराज्यपाल (एलजी) के रूप में विनय कुमार सक्सेना के कार्यकाल को जिम्मेदार बताया है। भारद्वाज ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि विनय कुमार सक्सेना के एलजी बनने के बाद से दिल्ली के हालात खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है। दिल्ली में अपराध दर सबसे यादा है। अधिकांश पुलिसकर्मी वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त हैं। भारद्वाज ने कहा कि बड़े समाज सुरक्षा गार्डों को नियुक्त करके अपनी सुरक्षा बनाए रखते हैं। लोगों ने चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, घर में चोरी और वाहन चोरी जैसी घटनाओं के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करना बंद कर दिया है क्योंकि कुछ होता ही नहीं है। आज दिल्ली के एक अस्पताल के अंदर हुई हत्या पर उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अस्पताल के अंदर प्रवेश के लिए सुरक्षा जांच नहीं कर सकते; यहां तक कि निजी अस्पतालों में भी सुरक्षा जांच के माध्यम से प्रवेश नहीं होता... कानून का डर ही अपराध को रोकता है। जब आपकी चार्जशीट की स्थिति इतनी खराब है कि अब आप 10फीसदी अपराधों के लिए चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते हैं, तो अपराधियों को पता है कि वे प्रबंधन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एलजी को रोजाना पुलिस स्टेशनों का दौरा करना चाहिए और औचक निरीक्षण करना चाहिए। यदि गलती मिले तो वहां कार्रवाई की जाए। आज कोई भी महिला शिकायत दर्ज कराने थाने नहीं जाना चाहती। क्या राजधानी में ऐसा होना चाहिए इस मामले पर केंद्र का कोई ध्यान नहीं है। अपने पोस्ट में, भारद्वाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दिल्ली पुलिस में कर्मचारियों की भारी कमी है और बल का एक बड़ा हिस्सा वीआईपी सुरक्षा में लगा हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 1,832 अपराधों के साथ दिल्ली में अपराध दर देश में सबसे अधिक है। केवल 30फीसदी मामलों में ही आरोप पत्र दायर किया जा रहा है। उन्होंने एलजी की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए पूछा, एलजी साहब ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या किया है।

डूयू ऑफिस में हुई तोड़फोड़, अब कमेटी करेगी मामले की जांच

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीती 13-14 जुलाई की रात को डूयू कार्यालय में हुई तोड़फोड़ के मामले पर एक्शन ले लिया है। डूयू ने इस मामले में एक जांच कमेठी बैठाई है। जो अब इस मामले की जांच करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) पर डूसू कार्यालय पर हमले का आरोप लगाया था। एबीवीपी ने कहा कि रविवार को डीयू के नॉर्थ कैंपस स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के कार्यालय पर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई से डूसू उपाध्यक्ष अभि दहिया सहित लगभग 40 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हमलावरों ने डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा का कार्यालय, विजिटर रूम, सचिव अपराजिता व सह-सचिव सचिन बैसला का कार्यालय तोड़ दिया। इस दौरान डूसू अध्यक्ष के कार्यालय में रखी प्रभु श्रीराम की मूर्ति भी टूट गई। एबीवीपी के एक कार्यकर्ता ने दावा किया कि उन्हें एक सुरक्षाकर्मी ने बताया कि तोड़फोड़ से पहले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डूसू कार्यालय परिसर में पीछे की तरफ स्थित एनएसयूआई से डूसू उपाध्यक्ष के कमरे में बैठकर शराब पी। उन्होंने बताया कि एनएसयूआई, डीयू के बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया है, उसका हम विरोध करते है। उन्होंने डीयू प्रशासन व दिल्ली पुलिस से मांग की कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल आपराधिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने कहा कि एबीवीपी इस पूरे मामले में डीयू कुलपति व दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलेगी। मामले में शामिल डूसू उपाध्यक्ष अभि दहिया व अन्य लोगों को पुलिस तुरंत गिरफ्तार करे। साथ ही, विश्वविद्यालय प्रशासन डूसू उपाध्यक्ष को तुरंत उनके पद से हटाएं।

तिहाड़ जेल की रिपोर्ट को आप ने किया खारिज, संजय सिंह बोले- भाजपा ने रचा केजरीवाल की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजन पर बवाल शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है. सोते समय उनका शुगर लेवल पांच बार 50 से नीचे चला गया. आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के दावे पर अब तिहाड़ जेल ने सवाल उठाया है. तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का 2 किलो वजन कम हुआ है. एम्स मेडिकल बोर्ड उनकी निगरानी कर रहा है. सूत्रों ने बताया कि जेल प्रशासन ने 'आप' मंत्रियों और नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि इस तरह की बातों से 'जनता भ्रमित होती है और गुमराह होती है.' जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक, 1 अप्रैल 2024 को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ आये तो उनका वजन 65 किलोग्राम था. 10 मई को जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से निकले तो उनका वज़न 64 किलोग्राम था. 2 जून को जब जेल में सरेंडर किया तो उनका वजन 63.5 किलोग्राम था. फिलहाल उनका वजन 61.5 (14जुलाई) किलोग्राम है.

तिहाड़ ने क्या कहा

जेल सुपरिटेंडेंट ने यह भी जानकारी दी है कि कम खाना खाने या कम कैलरी इनटेक के चलते भी वजन में गिरावट हो सकती है. अरविंद केजरीवाल का रोजाना सीनियर हेल्थ अफसरों की देख रेख में चेकअप होता है. साथ ही कोर्ट के आदेशानुसार, मेडिकल बोर्ड से परामर्श के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहती है. दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों, एक मौजूदा सांसद और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से निराधार

आरोप लगाए गए हैं. ये जेल प्रशासन को डराने के इरादे से झूठी जानकारी और जनता को भ्रमित करने की कोशिश है.

घर का खाना लौटा रहे केजरीवाल

सूत्रों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को घर का बना खाना मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन वह 3 जून से इसे नियमित रूप से वापस कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि एम्स का एक मेडिकल बोर्ड मुख्यमंत्री की लगातार निगरानी कर रहा है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बोर्ड के साथ नियमित संपर्क में हैं. उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को पत्र लिखकर केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर 'आप' के आरोपों को खारिज किया है. अपने पत्र में, जेल प्रशासन ने कहा कि 'इस तरह की बातें झूठी जानकारी और गुप्त उद्देश्यों से जनता को भ्रमित और गुमराह करती हैं ताकि जेल प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके.'

तिहाड़ को आम आदमी पार्टी का जवाब

वहीं, तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है. संजय सिंह ने कहा कि इसके साथ ही तिहाड़ अधिकारियों ने माना है कि केजरीवाल का वजन कम हुआ है. आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को आरोप लगाया था कि भाजपा केजरीवाल को जेल में रखकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है और उन्हें मधुमेह होने के कारण उचित इलाज नहीं मिल रहा है.

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल के 'बिना किसी वजह के 8.5 किलो वजन' कम होने पर चिंता जताई थी और दावा किया था कि जेल में उनका शुगर लेवल पांच बार से यादा 50 मिलीग्राम/डेसीलीटर से नीचे चला गया था.

कब गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को दिल्ली सरकार की अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 जून को तिहाड़ जेल से कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था. अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन वह सीबीआई मामले के सिलसिले में जेल में ही हैं.

सम्राट असोक महान मौर्य ने सिर्फ 84,000 स्तूप चैत्य ही नही बनाया, उन्होंने 52 ,00,000 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल भी बनाया जिसे अखंड भारत कहां जाता था नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला जैसे कई विश्वविद्यालय बनावाए थे जिससे विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने भारत आते थे ! ईसा पूर्व भारत में 500 BC से बौद्ध सभ्यता थी कोई भी भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नही करता था. ! सिकंदर आया लेकिन सम्राट असोक महान के दादा जी सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य से डर कर भाग गया सम्राट असोक महान के दौर में भारत पर हमला करना तो छोड़ो, विदेशी राजाओं को यह डर सताए रहता था कहीं सम्राट असोक महान उनके साम्राज्य पर आक्रमण ना कर दें सेंट्रल एशिया पूरा गंधारा, अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, नेपाल, म्यांमार, सब भारत का अभिन्न अंग थे. ! इसलिए कहा जाता है . था सूर्य चमकता मौर्यो का घनघोर बदरिया डरती थी था शेर गरजता सीमाओ पर बिजली भी आहें भरती थी.

शहीद मेजर आशीष धौंचक के परिवार में नहीं थम रहा कलेश, सरकारी नौकरी को लेकर मचा बवाल

पानीपत । पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौंचक के परिवार में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक तरफ उनकी पत्नी ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रही है। तो आशीष के माता-पिता भी बहू द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। पूरा विवाद अब सरकार की ओर से मिलने वाली सरकारी नौकरी के लिए हो रहा है। बता दें कि आशीष के माता-पिता नौकरी अपनी बेटी यानी आशीष की बहन को देना चाहते हैं। वहीं, सरकार द्वारा मिलने वाली नौकरी आशीष की पत्नी ज्योति को अनाउंस की गई है। आशीष की मां कमला ने प्रेस वार्ता कर फिर से अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि मामले में जो भी सत्य तथ्य है, उनकी जांच की जानी चाहिए। ससुराल वालों ने आरोप लगाया है कि बहू सरकार से मिलने वाली राशि मिलने के बाद अपने कमरे का ताला लगाकर अपने मायके चली गई है। कई माह बीत जाने के बाद वो वापस नहीं लौटी। यहां तक कि उसने और उसके परिवार वालों ने बातचीत तक करनी बंद कर दी। इसलिए सरकार उसे नौकरी न दे। वहीं, आशीष की पत्नी ज्योति ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने ससुराल वालों पर

उत्पीड़न, ननदों पर घर में दखल देने और ननद की नौकरी लगाने के लिए विवाद पैदा करने का भी आरोप लगाया है। वहीं ज्योति की सास यानी आशीष की मां कमला ने कहा कि उनकी बहू ज्योति ने आरोप लगाए हैं, कि घर में ननद और ननदोई की चलती है।

वे अपने परिवार समेत इसी घर में रहती है। कमला का कहना है कि इसकी सच्चाई ये है कि मेरी बेटियां और उनके पतियों की लोकेशन चेक करवा ली जाए वे जून महीने के अलावा यहां पर कभी नहीं आए। जबकि बहू ज्योति यानी आशीष की पत्नी का आरोप है कि उससे कभी फोन पर बात नहीं की गई। पोती का कभी हाल चाल नहीं जाना। कमला का कहना है कि उन्होंने हमेशा कॉल की है। बहू ने भी कभी उनसे बात करना पसंद नहीं किया। उसने कभी पोती से भी बात नहीं करवाई। बहू ज्योति का आरोप है कि सास सरकारी नौकरी अपनी बेटी को दिलवाना चाहती है। इस पर सास कमला ने कहा कि उसकी बहु उनके साथ नहीं रहती। वह घर पर भी ताला लगाकर गई है। सरकार से आखिरी चेक जब मिला, इसके बाद उसने पहले से ही प्लानिंग के तहत टैक्सी को बुक किया था। जिसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। कमला ने कहा कि उनकी बेटियां खुद आर्थिक तौर पर काफी मजबूत हैं। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बहू न हमारे साथ है न हमारी देखरेख करती है। तो उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। जब बेटियां ही देखभाल करेंगी तो नौकरी भी उनको ही मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा कोई दूसरा बेटा भी नहीं है। हमारा सहारा कोई नहीं है. बहू के घर छोड़कर जाने के बाद बेटियां ही अपने माता-पिता को संभालने के लिए घर पहुंचती हैं। तो जाहिर तौर पर नौकरी भी उन्हीं को मिलनी चाहिए। इसके अलावा, सास कमला ने कहा कि बहू ज्योति ने उन पर पोती का हालचाल न जानने और उससे बात न करने जैसे आरोप लगाए हैं, लेकिन सच यह है कि मैंने हमेशा ज्योति को कहा कि वो वामिनी से बात करवाए।

लेकिन उसने कभी वीडियो कॉल नहीं की। आशीष की शहादत के बाद जब वामिनी को वो यहां से खुद लेकर गई, उसके बाद खुद तो 2 बार आई। लेकिन उसे एक बार भी लेकर नहीं आई। इसलिए अब पोती को भी अपने पास रखना चाहती हूं और उसके लिए भी लड़ाई लड़ूंगी। साथ ही कहा कि ज्योति अगर दूसरी शादी के लिए कहती तो हम दूसरी शादी भी करवा देते। घर से बिन बताए हमें इस तरह मुश्किल में अकेले छोड़कर जाने की जरूरत नहीं थी।

ब्रजमंडल यात्रा को लेकर आपत्तिजनक कॉमेंट करने पर होगी कार्रवाई, एक पर किया मुकदमा दर्ज

नूंह । सावन के पहले सोमवार 22 जुलाई को जिला नूंह में प्रस्तावित ब्रजमंडल जल अभिषेक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के संबन्ध में ताहिर निवासी देवला के खिलाफ नूंह पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही शुरु कर दी है। उपपुलीस अधीक्षक सोनाक्षी सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया सैल नूंह में तैनात सिपाही मनोज कुमार ने 14 जुलाई को थाना साईबर क्राईम नूंह में एक दरखास्त ताहिर निवासी देवला के खिलाफ आगामी 22 जुलाई 2024 को जिला नूंह में होने वाली धार्मिक जलाभिषेक यात्रा के दौरान धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुष्प्रेरण द्वारा दंगे कराने की नियत से शत्रुता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचांने, आमजन को भडकाने व जलाभिषेक यात्रा में बाधा उत्पन करने बारे उक्त कमेंट अपनी फेसबुक आईडी पर डालने के संबन्ध में पेश की, जिस पर नूंह पुलिस ने तुरन्त संज्ञान लेते हुये ताहिर निवासी देवला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। उपपुलिस अधीक्षक नूंह ने आमजन से भी अपील कि है की किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म संप्रदाय को आहत करने की मंशा से पोस्ट के रूप में कोई भी वीडियो, फोटो या अभिलेख ना डालें। अगर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की भी कोई गलत अफवाह ना

फैलाएं। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा या फिर किसी के धर्म या जाति पर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर नूंह पुलिस सख्त एक्शन लेगी। नूंह पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। लोगों से भी अपील है कि समाज में आपसी भाईचारा बनाकर रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें । उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग सहयोग, आपसी भाईचारे व सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ही करें। गलत कार्य करने वालों और शरारती तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आगे कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/भडकाउ पोस्ट डालता है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मजदूरी का काम करता था, मां के बयान पर इत्तेफाकिया कार्रवाई

बास, हिसार ।

हरियाणा के हिसार के बास थाना क्षेत्र के गांव सोरखी में सोमवार को एक युवक का शव गांव के पशु अस्पताल में बरगद के पेड़ से लटका हुआ मिला। सुबह ग्रामीणों ने करीब 7 बजे शव को बरगद के पेड़ से लटका हुआ देखा तो इसकी सूचना सोरखी पुलिस चौकी को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया। एफएसएल की टीम ने मौके से जरूरी साक्ष जुटाए। बास थाना पुलिस द्वारा मृतक की मां की शिकायत पर इत्तेफाकिया कार्रवाई अमल में लाई गई है। गांव सोरखी निवासी मृतक की मां संतोष ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करती है। मेरे पति सुभाष चंद्र का करीब तीन साल पहले एक्सीडेंट हो गया था जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और घर पर ही रहता है। मेरा बेटा 27 वर्षीय मंजीत शादीशुदा था। उसकी पत्नी सीमा के साथ तलाक हो चुका

सुबह ग्रामीणों ने करीब 7 बजे शव को बरगद के पेड़ से लटका हुआ देखा तो इसकी सूचना सोरखी पुलिस चौकी को घटना की सूचना दी।

था और सीमा की मृत्यु भी हो चुकी है। सोमवार को सुबह करीब 5 बजे मेरा बेटा मंजीत घर से गया था और सुबह 7 बजे हमें सूचना मिली की मंजीत का शव पशु अस्पताल में बड़ के पेड़ पर लटका हुआ है। जिस सूचना पर वह व परिवार के सदस्य पशु अस्पताल में पहुंचे और देखा कि मंजीत का शव चुन्नी से लटका हुआ है। इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि मंजीत को किसी ने मारकर लटकाया है या अपने आप आत्महत्या की है। दो दिन पहले मंजीत की सोरखी निवासी पिंकी व उसके परिवार के सदस्यो के साथ कहासुनी हो गयी थी जिनका आपसी फैसला हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाए।

चिकित्सकों ने की हड़ताल, परेशान मरीजों ने रोड किया जाम, ये हैं प्रमुख मांग

चरखी दादरी । हरियाणा के चरखी दादरी में लंबित मांगों को लेकर जिले के 17 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात 60 चिकित्सकों ने सोमवार को दो घंटे की हड़ताल की। हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर इन चिकित्सकों ने सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी नहीं देखी। वहीं, उपचार से पहले लंबा इंतजार करने से खफा मरीज सिविल अस्पताल के बाहर आ गए और उन्होंने रोड जाम कर दिया। मरीजों और उनके तीमारदारों को समझा-बुझाकर आधे घंटे बाद जाम खुलवाया। दूसरी ओर दो घंटे की हड़ताल के चलते करीब 800 मरीज बिन उपचार करवाए ही घर लौट गए। बता दें कि दादरी शहर में दो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें सिविल अस्पताल व मातृ-शिशु अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा जिले में तीन सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) और 12 पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) हैं। इन सभी 17 केंद्रों की दैनिक ओपीडी करीब 2500 रहती है। सोमवार को चिकित्सकों ने सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी नहीं देखी और हड़ताल पर रहे।

चिकित्सकों ने 11 बजे के बाद सीट संभाली और इसके बाद ही मरीजों को उपचार मिल पाया। वहीं, चिकित्सकों की हड़ताल के चलते करीब 30 फीसदी ओपीडी प्रभावित रही और करीब 700 मरीजों को बिन उपचार के ही लौटना पड़ा। चिकित्सकों ने 11 बजे ओपीडी देखना शुरू किया और उसके बाद भी उनके कक्ष के बाहर मरीजों की भीड़ लगी रही। हालांकि उपचार से पहले मरीजों को दो घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ा और कई मरीज तो बिन उपचार के ही स्वास्थ्य केंद्रों से लौट गए। चिकित्सकों के लिए एक विशेषज्ञ कैडर का गठन किया जाए। गतिशील सुनिश्चित कॉरियर प्रगति (एसीपी) योजना लागू हो। एसएमओ की सीधी भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए। पीजी के लिए बॉन्ड राशि एक करोड़ से 50 लाख किए जाने आदि चिकित्सकों की मुख्य मांगें हैं। एचसीएमएस के आह्वान पर दो घंटे जिले के सभी चिकित्सक हड़ताल पर रहे। इस दौरान इमरजेंसी केस अटैंड किए गए जबकि ओपीडी बंद रखी गई। 11 बजे के बाद सामान्य दिनों की तरह ओपीडी शुरू कर दी गई। -डॉ. राजीव बैनीवाल, डिप्टी सीएमओ एवं जिला प्रधान, एचसीएमएसए।

भारतीय रेल ने रेलवे के लिये स्टार्टअप पहल के साथ नवाचार को बढ़ावा दिया

गोरखपुर ।

नवाचारों के माध्यम से रेलवे संचालन और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये, नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये, रेल मंत्रालय ने 13 जून, 2022 को रेलवे के लिए स्टार्टअप पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेलवे नेटवर्क में परिचालन दक्षता तथा सुरक्षा बढ़ाने के लिये भारतीय स्टार्टअप, एम.एस.एम.ई., व्यक्तिगत इनोवेटर्स, आर एंड डी संगठनों/संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों एवं उद्यमियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। इस पहल के तहत भारतीय रेल इनोवेशन पोर्टल https://innovation.indianrailways.gov.in/ पर भी लाइव कर दिया गया है। जुलाई 2024 तक, इनोवेशन में लगी कुल 1942 संस्थाओं ने भारतीय रेल के इनोवेशन पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर, एम.एस.एम.ई., आर एंड डी संगठन आदि शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने नवाचार नीति के विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध कार्यशालायें/ बैठकें/ वार्ता/वी.सी. का आयोजन किया है, जिसके परिणामस्वरूप स्टार्टअप्स/ नवप्रवर्तकों की अच्छी भागीदारी हुई है। रेल मंत्रालय को अब तक इनोवेशन पोर्टल पर खोले गए 28 समस्या विवरणों के लिये कुल 423 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। अब तक 15 समस्या विवरणों के लिये कुल 23 नवाचार परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई हैं। 23 स्वीकृत नवाचार परियोजनाओं की लागत लगभग रू. 43.87 करोड़ है, जिसमें पात्र संस्थाओं को रेलवे के अनुदान का हिस्सा लगभग रू. 10.52 करोड़ है। जिन समस्या विवरणों के लिये परियोजनायें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं, उनमें भारी ढुलाई वाले माल वैगनों के लिये बेहतर इलास्टोमेरिक पैड का डिजाइन, नमक जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिये हल्के वजन के वैगन, रेल तनाव निगरानी प्रणाली, सटीक निरीक्षण के लिए ट्रैक निरीक्षण प्रौद्योगिकी, ब्रोकेन रेल सिस्टम, ट्रैक सफाई मशीन, वी.पी.यू./पावर कार/ एस.एल.आर. में ऑडियो विजुअल अलार्म के साथ सेंसर आधारित लोड गणना उपकरण का विकास, सरलीकृत ओ.एच.ई. कैंटिलीवर डिजाइन, त्वरित बिंदु लॉकिंग क्लैम्प/ सिस्टम, वायरलेस नेटवर्किंग के साथ भारतीय रेल के कोचों के लिये सेंसर आधारित फायर/स्मोक डिटेक्शन प्रणाली का विकास, भारतीय रेल पर बुक किये गये कंसाइनमेंट्स की सुरक्षा के लिये ई-सील प्रणाली, कम दृश्यता एवं संचार की कमी के कारण शंटिंग के दौरान असुरक्षित स्थितियों से बचने के लिये तकनीकी समाधान का विकास, लोको पायलट और गार्ड को कॉशन की जानकारी देना, एल.वी.पी.एच. कोचों की छतों पर फ्लेक्सी सौर पी.वी. पैनलों के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का प्रावधान, वायरलेस नेटवर्किंग के साथ भारतीय रेल के कोचों के लिये सेंसर आधारित फायर/स्मोक डिटेक्शन प्रणाली का विकास (द्वितीय चरण सम्मिलित)। उपरोक्त समस्या विवरणों में नवाचारों से न केवल रेलवे परिचालन में सुधार होगा, बल्कि सुरक्षा और सुविधायें भी बढ़ेंगी।

महिला की बरामदगी न होने से पीड़ित परिजन परेशान

कमिश्नरेट पुलिस पर पीड़ित को अभी भी भरोसा

कानपुर।

सोमवार को परिवार की महिला के लापता उपरांत अपहरण की आशंका व पुलिस की तरफ से किसी भी तरह से कारवाई नहीं किए जाने से परेशान शहर के गोपाल विहार सिविल लाइंस निवासी पीड़ित परिवार कानपुर प्रेस क्लब पहुंच प्रेस वार्ता करके अपनी आपबीती बताई। पीड़ित परिजन ने पत्रकारों को बताया कि विमल सोनी वाल्मीकि द्वारा नशीला पदार्थ पिलाकर मेरी औरत का अपहरण किया गया था इसके बाद पुलिस द्वारा 25 जून को ट्रेनर की कार बरामद की गई जिसमें महिला का टूटा हुआ क्लेचर जिम, टावल मोबाइल की सिम ट्रे और दोनों सिम तथा रस्सियां भी बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की । पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रेनर के संबंध जिला अधिकारी आवास कार्यालय दोनों जगह थे तब से लेकर आज दिनांक 14 जुलाई 2024 तक पूरे 21 दिन हो चुके हैं। पुलिस के पास सिर्फ 24 जून के अलावा उस ट्रेनर की कोई जानकारी नहीं है । पुलिस ने महिला और ट्रेनर की कॉल डिटेल निकलवाने पर पाया कि एक महीने में ट्रेनर और महिला के बीच दो से चार बार बात हुई थी, जिसमें पुलिस ने यह मान लिया कि महिला अपनी स्वेच्छा से गई है। अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई में रुचि न लेते हुए सिर्फ परिवार वालों से यह कह रहा है कि आप धैर्य रखिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी जीवित भी है या नहीं। महिला न ही घर में से कोई एक्स्ट्रा जेवर या पैसे लेकर गई है। इसके अलावा ट्रेनर की कार में मिली वस्तुएं घटनाक्रम को संदिग्ध दर्शाती है। महिला के पति राहुल गुप्ता ने बताया कि ऐसे में मेरी पत्नी की बरामद वस्तुएं पत्नी के साथ किसी अनहोनी की आशंका की ओर इशारा करती दिखाई दे रही है। परिवार ने मीडिया के जरिए शासन प्रशासन से यह गुहार लगाई है कि कम से कम मेरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए । मेरे मामले की जांच में देरी से व महिला के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होगी ,तो इससे पुलिस प्रशासन की अकृमणयता साबित होगी और लापरवाह व दोषी पुलिसकर्मियों की शिकायत प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से कर उन पर कार्रवाई को बाध्य होंगे। इसी के साथ हमारा अगला कदम हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी न्याय की गुहार लगाएंगे।

कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण बनी एनडीए सरकार - सांसद रमेश अवस्थी

कानपुर।

देश की जनता जानती है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है। कांग्रेस संविधान की हत्या करने वाली पार्टी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संविधान बदलने के झूठ को जनता के बीच प्रचारित कर जनता को भ्रमित किया। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी में 2014, 2017, 2019 और 2022 में बड़ी सफलता प्राप्त की है। देश वासियों के प्रेम की बदौलत ही 2024 में भी भाजपा ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की सरकार में ध्वस्त कानून व्यवस्था, गुंडाराज, परिवारवाद और कांग्रेस को संविधान बदलने के झूठे प्रचार को पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर कांग्रेस और सपा का सच बताएं। ये बातें सांसद रमेश अवस्थी ने किदवई नगर व छावनी विधानसभा के मतदाता अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहीं। सोमवार को किदवई नगर और छावनी विधान सभा में अलग अलग मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी, दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह एवं विधायक महेश त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनवाने के लिए सांसद रमेश अवस्थी ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत व अभिनंदन किया। विधानसभा के प्रबुद्ध एवं प्रभावशाली मतदाताओं को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया।पार्टी नेताओं ने पुष्प वर्षा कर मतदाताओं का अभिनंदन कर आभार जताया। विधायक महेश त्रिवेदी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कह कर देश की जनता को अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या घोषित किया गया तो विपक्ष को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि देश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मोदी की गारंटी ने हमें जिताया और इंडिया गठबंधन की गारंटी ने जनता को बहकाया है। यदि भोले भाले मतदाता बहकावे में ना फंसते तो हम नया इतिहास बनाते।

भारतीय एसी उद्योग का आकार अगले चार साल में दोगुना होने का अनुमानः ब्लू स्टार

नई दिल्ली।

भारत में एयर कंडीशनर (एसी) उद्योग लगभग 27,500 करोड़ रुपए (3.3 अरब डॉलर) का है और इसके अगले चार साल में दोगुना होने की संभावना है। एसी कंपनी ब्लू स्टार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही है। ब्लू स्टार के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) वीर एस आडवाणी ने कहा कि भारतीय एचवीएसीएंडआर (हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटिंग) उद्योग तेजी से वृद्धि के लिए तैयार है। यह वृद्धि घरेलू एसी की कम पहुंच और उच्च व्यय योग्य आय वाले मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या, विशेष रूप से तीसरी, चौथी और पांचवीं श्रेणी के शहरों के बाजारों से आने वाले उपभोक्ताओं जैसे कारकों से प्रेरित होगी। आडवाणी ने 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में कंपनी के शेयरधारकों से कहा, भारतीय एसी उद्योग (घरेलू और वाणिज्यिक दोनों) का वर्तमान मूल्य लगभग 27,500 करोड़ रुपए है, जो अगले चार वर्षों में दोगुना होने का अनुमान है। कंपनी अपने भविष्य के व्यावसायिक परिदृश्य के बारे में आशावादी है, क्योंकि मौसम का रुझान बदल रहा है, जिससे गर्मियां बढ़ रही हैं, तथा आवासीय और वाणिज्यिक एयर-कंडीशनिंग में एक नया और मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो भी सामने आया है।

आडवाणी ने कहा कि ब्लू स्टार ने अपनी मुख्य क्षमताओं को मजबूत करने, नई क्षमताएं हासिल करने, नई प्रक्रियाएं बनाने और नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तीन वर्षीय रणनीतिक योजना शुरू की है।

बजट में किसानों के लिए हो सकते हैं कई बड़े ऐलान, बढ़ सकती है केसीसी लिमिट

बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 (मंगलवार) को चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता के साथ-साथ देश के अन्नदाताओं यानी किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि इस आम बजट में देश के अन्नदाताओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है।

साथ ही मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने समेत कई रियायतों की भी घोषणा कर सकती है। दरअसल पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि सरकार अन्नदाताओं के हित में बड़े फैसले ले। इससे देशभर के किसानों में यह साफ संदेश जाएगा कि सरकार कृषि को लेकर गंभीरता से काम कर रही है।

क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा बढ़ाने की उम्मीद

फिलहाल किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कृषि लोन 7 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिल रहा है, जिसमें सरकार 3 फीसदी की सब्सिडी देती है। यानी किसानों को यह लोन 4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिलता है। वहीं बढ़ती महंगाई के साथ-साथ कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार 3 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए कर सकती है।

टैक्स दरों में कटौती संभव

बता दें कि केंद्र सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर तस्ज्ञ लगाती है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर तस्ज्ञ हटाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दे। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार बजट में कृषि उपकरणों पर तस्ज्ञ दरों में भी कटौती कर सकती है या फिर ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है।

पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ेगी राशि

सूत्रों की माने तो आम Budget 2024 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। दरअसल मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए दे रही है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि लगातार बढ़ रही महंगाई और किसानों की बढ़ती लागत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए की 3 किस्त ट्रांसफर करती है। पिछले महीने सरकार ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की थी। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ देशभर के 11 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद किसानों को मिल रहा है।

नई-तकनीक का इस्तेमाल

देश में हर क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अभी नई तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बजट में कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर कोई घोषणा होने की संभावना है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोई नया प्रोग्राम शुरू कर सकती है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने फरवरी में पेश अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाया था। केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ऐसे में 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट में किसानों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार की ओर से कुछ घोषणा हो सकती है।

सोने-चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव, चेक करें 10 ग्राम गोल्ड का रेट

बिजनेस डेस्क ।

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानि सोमवार को सोने-चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत सुस्त रही। सोने के वायदा भाव 73,150 रुपए के करीब, जबकि चांदी का वायदा भाव 92,850 रुपए के करीब कारोबार कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव की भी शुरुआत सुस्त रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आज 164 रुपए की गिरावट के साथ 73,105 रुपए के भाव पर खुला। खबर लिखे जाने के समय यह 73,143 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 73,144 रुपए के भाव पर दिन का उच्च और 73,082 रुपए के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। सोने के वायदा भाव ने इस साल 74,442 रुपए के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रैक्ट आज 206 रुपए की गिरावट के साथ 92,903 रुपए पर खुला। खबर लिखे जाने के समय यह कॉन्ट्रैक्ट 267 रुपए की गिरावट के साथ 92,842 रुपए के भाव पर कारोबार कर रहा था। इस समय इसने 92,903 रुपए के भाव पर दिन का उच्च और 92,828 रुपए के भाव पर दिन का निचला स्तर छू लिया। इस साल चांदी के वायदा भाव ने 96,493 रुपए के भाव पर सर्वोच्च स्तर छू लिया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने व चांदी के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई।

Come& पर सोना 2419.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस 2,420.70 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 6.60 डॉलर की गिरावट के साथ 2,414.10 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। Come& पर चांदी के वायदा भाव 31.10 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला क्लोजिंग प्राइस 31.16 डॉलर था। खबर लिखे जाने के समय यह 0.08 डॉलर की गिरावट के साथ 31.08 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

अब रेमण्ड ने भी शुरू की आईपीओ की तैयारियां, कंपनी ने उठाए ये बड़े कदम

बिजनेस डेस्क। शेयर बाजार की ऐतिहासिक रैली में आईपीओ का तांता लगा हुआ है. कई बड़ी कंपनियां आईपीओ लेकर आ चुकी हैं और कइयों ने तैयारी पूरी कर ली है. आईपीओ लाने वालों कतार में टाटा से लेकर बजाज और अंबानी से लेकर अडानी शामिल हैं. अब इस लिस्ट में एक और बड़े कारोबारी घराने रेमण्ड का नाम जुड़ने वाला है. खबरों की मानें तो रेमण्ड समूह भी बाजार में आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है. रेमण्ड समूह से ये प्रस्तावित आईपीओ रेमण्ड लाइफस्टाइल लिमिटेड का हो सकता है. ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी ने आईपीओ की तैयारियां तेज कर दी है. ईटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रेमण्ड लाइफस्टाल को अगले महीने शेयर बाजार में लिस्ट कराया जा सकता है. रेमण्ड समूह में हाल ही में कंपनियों व कारोबार का पुनर्गठन शुरू हुआ है. पुनर्गठन के तहत रेमण्ड लाइफस्टाइल को डिमर्ज किया गया है. अब रेमण्ड लाइफस्टाइल 9,286 करोड़ रुपये के रेमण्ड समूह की एक स्टैंडअलोन कंपनी है. रेमण्ड

लाइफस्टाइल को डिमर्ज करने समेत रेमण्ड समूी के पुनर्गठन की योजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने पिछले महीने ही मंजूरी दी है. पुनर्गठन की योजना के तहत शेयरधारकों को रेमण्ड के हर 4 शेयर के बदले रेमण्ड लाइफस्टाइल के 5 शेयर मिलने वाले हैं. उसके बाद अब कंपनी ने आईपीओ की तैयारियों के तहत कई नई नियुक्तियां की है. कंपनी ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत नायर, आईसीआईसीआई के पूर्व चेयरमैन जीसी चतुर्वेदी, एबॉट की बोर्ड मेंबर अनीषा मोटवानी और रेमण्ड के डाइरेक्टर दिनेश लाल को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है. आईपीओ की तैयारी से जुड़े सूत्रों ने ईटी को बताया है कि ये नियुक्तियां लिस्टिंग की योजना का हिस्सा हैं. इन सभी लोगों को इसी महीने की शुरुआत में नियुक्त किया गया है. अभी रेमण्ड लाइफस्टाइल में कुछ और नियुक्तियां होने वाली हैं. रेमण्ड समूह के चेयरमैन गौतम सिंघानिया रेमण्ड लाइफस्टाइल के प्रबंध निदेशक का पद संभाल सकते हैं. रेमण्ड लाइफस्टाइल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कटारिया भी नव गठित बोर्ड का हिस्सा बनाए जा सकते हैं.

निवेशकों की बढ़ती भागीदारी से 130फीदी बढ़ा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन, वित्त वर्ष 2024-25 में 16634 करोड़ रुपये रही वसूली

बिजनेस डेस्क।

भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाईयों को छू रहा है. भारतीय बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है.

ऐसे में शेयर बाजार में शेयरों के खरीद फरोख्त पर टैक्स से होने वाली सरकार की कमाई में भी भारी इजाफा देखने को मिला है. वित्त वर्ष 2024-25 के पहले तीन महीने और 11 दिनों में 11 जुलाई 2024 तक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से सरकार को होने वाली कमाई में जोरदार उछाल देखने को मिला है. इस अवधि के दौरान सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के जरिए सरकार को 16,634 करोड़ रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ है जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के समान अवधि में वसूले गए एसटीटी के दोगुने से ज्यादा है. सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में 11 जुलाई 2024 तक शेयरों के खरीदने बेचने पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से सरकार को 16,634 करोड़ रुपये की कमाई हुई है जो कि वित्त वर्ष 2023-24 के समान अवधि में 7285 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ था. यानि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले मौजूद वित्त वर्ष में इस अवधि तक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स

कलेक्शन में 128.33 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी कारोबारी सत्र 28 मार्च को बीएसई सेंसेक्स 73,651 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 22,327 अंकों पर क्लोज हुआ था. तो निफ्टी का मिडकैप इंडेक्स 48,000 के आंकड़े पर बंद हुआ था. पिछले साढ़े तीन महीने में बाजार में आई तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस लेवल से सेंसेक्स में 7100 यानि करीब 10 फीसदी, निफ्टी में 2300 और निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 28 मार्च के लेवल से 9600 अंकों से ज्यादा का उछाल आ चुका है. और इसका श्रेय भारतीय बाजारों में रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को जाता है जिससे एसटीटी कलेक्शन बढ़ा है.

वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स-निफ्टी ने कई नए कीर्तिमान बनाए. 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले दिन जब ये साफ हो गया कि सत्ताधारी दल बीजेपी को इन चुनावों में बहुमत नहीं मिलने जा रही है तो निवेशक मायूस हो गए. इसके चलते भारतीय शेयर बाजार में गिरावट की सुनामी देखने को मिली. लेकिन जैसे ही तस्वीर साफ होने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में गठबंधन सरकार बनेगी तो बाजार ने गजब की वापसी की. उसके बाद निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के चलते सेंसेक्स 80000 और निफ्टी 24000 अके आंकड़े को पार कर गया.

और इसका फायदा भारत सरकार को मिलता नजर आ रहा है. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में डबल उछाल देखने को मिला है.

अनागरिक
गीता भारती
प्रखर वक्ता, कुशल
रणनीतिकार आदरणीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी
को जन्मदिन
की हार्दिक शुभकामनाएँ
21 जुलाई 2024
रिपब्लिकन
मज़दूर संगठन
निवेदकः-
किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी
विजय कुमार भारती
किराड़ी जिला, महासचिव/पत्रकार